संचिका सं0-पी0एम0यू0/बी0सी0डी0-16/2016.......9954(भ)/ 313

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 06/10/2016

विषयः- भवन निर्माण विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आवंटित कार्यो की अद्यतन समीक्षात्मक टिप्पणी के संबंध में।

प्रसंगः- विभागीय पत्रांक 8147(भ)अनु0 दिनांक 23.08.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु 154 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इन कार्यो की माह अगस्त, 2016 तक की प्रगति की स्थिति निम्नवत हैः-

(1) **भौतिक प्रगतिः-**

- कुल 154 योजनाओं में से 60 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है, जिसकी विवरणी परिशिष्ट **'क'** पर द्रष्टव्य है।
- 34 कार्य प्रगति में है, जिसकी विवरणी परिशिष्ट **'ख'** पर द्रष्टव्य है।
- 52 योजनाएं निविदा/प्राक्कलन/मिट्टी जांच के चरण में है, जिसकी विवरणी परिशिष्ट **'ग'** पर द्रष्टव्य है।
- 5 योजनाओं के लिए स्थल समस्या है, 2 योजना माननीय न्यायालय में है एवं 1 योजना स्थगित है, जिसकी विवरणी परिशिष्ट **'घ'** पर द्रष्टव्य है।

(2) **वित्तीय प्रगतिः-**

- वित्तीय वर्ष 2016-17 में माँग संख्या-3 में कुल 3300.01 लाख का बजट उपबंध है, जिसके विरूद्ध 1174.97 लाख रुपये का व्यय हुआ है।

(3) **प्रशासी विभाग के ध्यानाकर्षण हेतु मुख्य मुद्देः-**

- जिन योजनाओं के लिए स्थल अनुपलब्ध है, उनमें शीघ्र स्थल उपलब्ध कराया जाए।
- इस वित्तीय वर्ष में 30.00 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकता होगी। तद्नुसार अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए।
- आयुक्त कार्यालय, मुंगेर के आवास के लिए मांग सं0-3 में स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जाय।

(4) **अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था**

- भवन निर्माण विभाग के स्तर पर आपके विभाग की योजनाओं के अनुश्रवण के लिए श्री रविन्द्र प्रसाद सिंह, उपनिदेशक-2 को दायित्व दिया गया है जिनका ई-मेल dd2.bcd@gmail.com तथा मोबाईल नं0 9430965732 है।
- भवन निर्माण विभाग द्वारा Project Management Information Systemविकसित किया गया है, जो विभाग के वेबसाईट पर उपलब्ध है। इस अनुश्रवण व्यवस्था में सभी योजनाओं की अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय स्थिति Upload करायी जा रही है। आपसे अनुरोध है कि प्रशासी विभाग के स्तर से भी योजनाओं की प्रतिवेदित भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा की जाए। इस क्रम में किसी बिन्दु पर इस विभाग के स्तर से कार्रवाई अपेक्षित हो तो कृपया अवगत कराया जाए।
- उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय पदाधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक में भी इस समीक्षा टिप्पणी में अंकित बिन्दुओं पर समीक्षा की जाएगी। उस बैठक में अद्यतन विवरणी के साथ स्वयं या नोडल पदाधिकारी को भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्ति करने की कृपा की जाए।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

21/9

(अमृत लाल मीणा)

सरकार के प्रधान सचिव।